IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
CWJC No.4849 of 2006

Narendra Nath Mishra, S/o Late Nilamber Mishra, Resident of Village and P.O. Gandhwar, P.S. Sakari, District Madhubani, at present residing in Bimla Tower, Flat No. 14, Hanuman Nagar, New Punaichak, P.S. Shastrinagar, Patna-23, Phone No. 2287928 and office in the Prince Chamber, Table No.1 in front of Advocate Association Library High Court, Patna.

--------- Petitioner

Versus

1. The State of Bihar.
2. Commandant General Bihar Home Guards H.Q. Chhajubagh, Patna.
3. Deputy Commandant General Bihar Home Guard, H.Q. Chhajubagh, Patna.
4. Commandant, Bihar Home guard, Head Quarter Chhajubagh, Patna.
5. District Commandant, Bihar Home Guards, Dhanbad.
6. Commandant, C.T.I., Bihta.
7. Secretary Home (Special) Bihar, Patna.
8. Accountant General, Bihar, Patna.

--------- Respondents

For the Petitioner	:-	Mr. Narendra Nath Mishra (in person)
For the State	:-	Mr. H.P.Singh,Advocate.(SC-5)
For the Accountant General	:-	Mr. J.P. Karn, Sr. Advocate

P R E S E N T

THE HON'BLE MR. JUSTICE MIHIR KUMAR JHA

Mihir Kr. Jha, J. Heard counsel for the parties.

The prayer of the petitioner in this writ application reads as follows:-

"1. *That this is an application for issuance of appropriate writ in the nature of certiorari to quash the notice dated 28.11.2005 vide memo no. 2700 conveyed by commandant Bihar Home Guards Patna and final order dated 30-01-2006 vide FO No. 29/2006 and memo*

no. 173 passed by Deputy Commandant General Bihar Home Guards Patna. Through which order for deducting Rs.100/-(one hundred) P. M. in 14 (fourteen) installment total Rs.1400/- (One thousand four hundred) from already sanctioned full pension to the petitioner after finding service record thoroughly satisfactory by competent authority and P.P. O. issued by A. G. Bihar, Patna vide his memo no. 21040 dated 09-01-2001 which is wrong, illegal and against Bihar Pension Rules 43(b)(a)(i)(ii) and Bihar Pension Rule 139(b) and (c) and Petitioner further prays for issuance of appropriate writ in the nature of certiorari to quash the order dated 30-01-2006 of the Deputy Commandant General for not to make payment any amount to the Petitioner in respect of T. A. Claims of session 1980-81 to 1983-84 which are already passed, Sanctioned by competent authority and order by this Hon'ble Court in CWJC No. 8941/95 by Hon'ble Mr. Justice S. N. Jha on 17-1-97 as well as prayer of the petitioner for payment of admitted T. A. Claims along with interest has already been again allowed by this Hon'ble Court in CWJC No. 5227/2002 by order dated 7-9-2005 passed by Hon'ble Mr. Justice Narayan Roy which are annexed as Annexure 1 to 5 of this petition."

It appears that the petitioner, a police personnel, was subjected to a departmental

proceeding for certain misconduct vide Memo of Charge dated 20th January, 1997 relevant portion whereof reads as follows:-

''**आरोप–पत्र**

गुल्म समादेषक नरेन्द्र नाथ मिश्रा, बिहार गृह रक्षावाहिनी, धनबाद सम्प्रति चाईबासा के विरूद्ध घोर अनुशासनहीनता कर्तव्यहीनता, धोखाधड़ी तथा जालसाजी का आरोप लगाया जाता है कि :–

1) धनबाद जिला में पदस्थापन के दौरान इनके द्वारा समर्पित यात्रा भत्ता विपत्र इन्होंने जिला समादेष्टा धनबाद (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी) से पारित नहीं कराकर प्रमंडलीय समदिष्टा हजारीबाग द्वारा पारित कराया जो नियमानुकुल नहीं है।

2) इन्होंने यात्रा भत्ता विपत्र के साथ निजि देनिन्दनी तथा यात्रा करने हेतु सक्षम पदाधिकारी का आदेश प्रस्तुत नहीं किया।

3) इन्होने यात्रा भत्ता विपत्र का कालम 22 फाड़कर हटा दिया है।

4) यात्रा भत्ता विपत्र के कालम 11 अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यात्रा यात्रा टेकर से किया गया है। और बाद में लिप्त लेखन कर मोटर साईकिल तथा दोस्त के मोटर साइकिल से यात्रा दिखाया गया है। परन्तु दोस्त का नाम तथा मोटर साइकिल न अंकित नहीं है।

5) यात्रा भत्ता विपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि इन्होंने एक माह मे कम से कम 2302 कि0मी0 तथा अधिकतम 8196 कि0मी0 यात्रा किया है। जो विश्वसनीय नहीं है।

6) इनके द्वारा किये गये यात्रा का ब्योरा निम्नवत है।

मह	*तय की गयी दूरी कि0मी0*	*विराम की अवधि*
सितम्बर 81	*2504 कि0मी0*	*14 दिन*
अक्टूबर 81	*5125 कि0मी0*	*27 दिन*
नवम्बर 81	*3591 कि0मी0*	*19 दिन*
दिसम्बर 81	*5373 कि0मी0*	*29 दिन*
जनवरी 82	*5642 कि0मी0*	*27 दिन*
फरवरी 82	*6727 कि0मी0*	*28 दिन*
मार्च 82	*5253 कि0मी0*	*26 दिन*
अप्रील 82	*6225 कि0मी0*	*30 दिन*
मई 82	*7935 कि0मी0*	*29 दिन*
जून 82	*6381 कि0मी0*	*29 दिन*
जूलाई 82	*5394 कि0मी0*	*29 दिन*
अगस्त 82	*8196 कि0मी0*	*27 1/2 दिन*

सितम्बर 82	*6188 कि0मी0*	*23 1/2 दिन*
अक्टुबर 82	*3739 कि0मी0*	*19 दिन*
नवम्बर 82	*3145 कि0मी0*	*22 दिन*
दिसम्बर 82	*2302 कि0मी0*	*15 दिन*
	83710 कि0मी0	*393 दिन*

7) इन्होंने दिनांक 18–4–82 को 240 कि0मी0, 19–4–82 को 269 कि0मी0 20–4–82 एवं 22–4–82 को 453 कि0मी0 23–4–82 को 302 कि0मी0 25/26–4–82 को 410 की0मी0 दिनांक 27/28–4–82 को 378 कि0मी0 यात्रा किया है। जो विश्वसनीय नहीं है।

8) इन्होंने जालसाजी कर वर्ष 1981 से 1983 तक का कुल 35823.32 पैसे का यात्रा भत्ता प्रस्तुत किया। इस प्रकार इन्होंने गलत यात्रा भत्ता प्रस्तुत किया है। जो बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के नियम (कामेन्ट रूल) (डी) के अन्तर्गत सेवा से बरखास्तगी का आरोप बनता है।"

For such charges, the petitioner was subjected to a departmental proceeding wherein the enquiry officer by his enquiry report dated 26.5.1999 had held all the eight charges to have been proved against him. Thereafter, the petitioner was subjected to an order of punishment dated 13.7.1999 passed by the Deputy Commandant General, Home Guards which was also affirmed in appeal by the appellate authority whereafter the petitioner had moved this Court in CWJC No. 5227 of 2002 and this Court having noticed that the said order of punishment was passed without supply of copy of the enquiry report had set aside both of them and had remitted the matter back to the said authority to proceed in the matter afresh as would be

apparent from the operative portion of the order of this Court dated 7.9.2005 which reads as follows:-

> *"In case at hand it appears that the copy of the enquiry report was not made available to the petitioner and thus, it amounted to denial of reasonable opportunity.*
>
> *The orders impugned in the background of the ratio, as referred to above, is thus held to be violative of the principles of natural justice and wholly without jurisdiction. This writ application on these score alone, in my opinion, should succeed.*
>
> *In the result, this writ application is allowed. Orders impugned are set aside.*
>
> *However, the matter is remitted back to the disciplinary authority to proceed in the matter afresh, if so advised."*

From reading of the petitioner's show-cause reply dated 5.12.2005 (Annexure-11), it would appear that the petitioner was supplied with a copy of the enquiry report with a show-cause notice contained in memo no. 2700 dated 28.11.2005 but the petitioner instead of giving comments/reaction to the findings recorded against him in respect of charges in the enquiry report had in his reply dated 5.12.2005(Annexure-11) tried to educate the disciplinary authority as with regard to the scope of Rule 43b of Bihar Pension Rules and the interpretation of the High Court order dated 7.9.2005. In fact, the petitioner in his

such reply dated 5.12.2005 had dwelt only on the scope of judicial review, pension rules and the judgment of the Apex Court in the case of Mohd. Idris Ansari by summing up the whole issue in the following words:-

> *"इस प्रकार नियम 43 (a) and (b) के (a)ii के अवलोकन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णित केस में पारित आदेश के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि वर्तमान परीस्थिति में पेन्सन कटौती/जप्ति से सम्बन्धित आदेश मेरे विरूद्ध नियमानुसार नहीं पारित किया जा सकता है।*
>
> *अतः निवेदन करूँगा कि मेरे द्वारा समर्पित आवेदन दि0 1. 10.2005 के आलोक में यात्रा भता तथा कटौती किये रकम सूद समेत भुगतान कराने की कार्रवाई की जाय।"*

This show-cause reply was considered by the disciplinary authority and the authority having found that the petitioner had not even offered his comment/reaction to the findings recorded in the enquiry report much less denying them, had rejected such explanation of the petitioner and thereafter had passed an order of punishment dated 30.1.2006 in the following terms:-

> सैन्यादेश संख्या–29/2006
>
> श्री नरेन्द्र नाथ मिश्रा, कंपनी कमांडर (सेवा निवुत) बिहार गृह रक्षा वाहिनी, धनबाद सम्प्रति चाईवासा के विरूद्ध गलत यात्रा भत्ता विपत्र सर्मपित करने के आरोप में विभागीय कार्यवाही सं0 1/97 चलाई गई थी। इसमें री मिश्रा पर लगाए गऐ सभी आरोप प्रमाणित हुए थे। फलतः सैन्यादेश संख्या 519/99/ज्ञापांक 2696 दिनांक 13.07.99 द्वारा अंतिम आदेश पारित किया गया था। इस आदेश द्वारा छः माह के वेतनवृद्धि के सम्प्रहरण करने तथा यात्रा भत्ता के सभी दावों की जांच की मात्र सही दावों का ही मान्य करने का आदेश दिया गया

था।

श्री नरेन्द्र नाथ मिश्रा द्वारा उक्त सैन्यादेश सं0–519/99 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 5227/02 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 07.9.05 को पारित अपने आदेश में विभागीय कार्यवाही सं0 1/97 में अंतिम आदेश निर्गत करने के पूर्व संचालन पदाधिकारी के मंतव्य की प्रति श्री मिश्रा को उपलब्ध कराकर स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं करने के लिए सरकार को दोषी माना तथा सैन्यादेश सं0 519/99 को रद्द कर दिया (सेट एसाइड) एवं मामले को पुनः प्रारंभ करने का आदेश दिया।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विभागीय कार्यवाही के संचालन की प्रक्रिया तथा दिए गए दंड के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है। आदेश मे केवल यही कहा गया है कि विभागीय कार्यवाही में अंतिम आदेश पारित करने के पूर्व संचालन पदाधिकारी का मंतव्य री मिश्र को उपलब्ध नहीं कराया गया और उन्हें अपने बचाव का अवसर नहीं दिया गया जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लंघन हुआ है।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मुख्यालय, पटना के ज्ञापांक 2700 दिनांक 28.11.05 द्वारा संचालन पदाधिकारी के मंतव्य की प्रति भेजते हुए उनके मामले को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 के तहत् पेशन कटौती के मामले में परिणत करने के संबंध में श्री मिश्रा से स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री मिश्रा का स्पष्टीकरण दि0 8.12.05 को कार्यालय में प्राप्त हुआ इनका स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया।

अतः समीक्षोपरान्त इस मामले को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 में परिणत करते हुए इनके पेंशन सं रू0 100/– (एक सौ) प्रतिमाह की दर से कुल 14(चौदह) किस्तों में कुल रू0 1400/– (एक हजार चार सौ) कटौती करने सैन्यादेश सं0 519/99 में कटौती की गई छः माह के वेतन वृद्धि का भुगतान करने तथा यात्रा भत्ता के रूप में कोई राशि का भुगतान नहीं करने का आदेश दिया जाता है।

ह0/–
(अजीत दत्ता)
उपसमाहर्त्ता
बिहार गृह रक्षावाहिनी, पटना।

मुख्यालय, बिहार गृह रक्षवाहिनी, पटना।
ज्ञापांक 173/पटना, दिनांक 30 जनवरी 2006 ई0,
डी0पी0 1–97
प्रतिलिपिः– सैन्यादेश प्रभारी, पेंशन शाखा/कंपनी कमांडर पठन/विभागीय कार्यवाही

The petitioner appearing in person while assailing the aforesaid impugned order of punishment dated 30.1.2006 had submitted that

as he had superannuated from service on 31.1.2000, he could not have been subjected to any further departmental proceeding and therefore, the impugned order inflicted against the retired person like the petitioner was unsustainable on this ground alone. In this context, he had placed reliance on the judgment of this Court in the case of ***Kauleshwar Pd. Sharma @ K.P. Sharma Vs. The Bihar State Elec. Board & Ors.*** reported in ***2009(1) PLJR 657*** to claim immunity on account of cessation of master-servant relationship. He had also referred to the judgment of the Apex Court in the case of ***State of Bihar & Ors. Vs. Mohd. Idris Ansari*** reported in ***1995(2) PLJR 51 SC.***

In the opinion of this Court, the submission of the petitioner lacks merit because it stands settled by the judgment of the Full Bench of this Court in the case of ***Shambhu Saran Vs. The State of Bihar & Ors.*** reported in ***2000(1) PLJR 665*** that a proceeding initiated prior to the retirement can still be continued for the purposes of Rule 43 of Bihar Pension Rules. The Full bench in that context had laid down the law in the following words:-

> *"........Accordingly in our view, it is open to an authority concerned to continue with a*

disciplinary enquiry which was initiated before his retirement. In our opinion, once such proceeding is statrted, even if the person concerned retires from service, such proceeding can be continued and it is not required that there must be any Government order to that effect before it can be allowed to continue. No such condition has been laid down in rule 43 in respect of a case where such a proceeding has already been initiated as required by the three conditions in respect of initiation of a fresh proceeding after such retirement. We cannot import the requirement of such a condition which is not in the rules. This would be against the principle of cassus omissus. If we accept the contention that such an order of the Government is required before such proceeding can be continued, then we shall be introducing a condition in the rule, which the rule does not provide for..........."

In this case also, the authorities after the order of this Court dated 7.9.2005 in CWJC No. 5227 of 2002 filed against the order of punishment of the petitioner dated 13.7.1999 and appellate order dated 24.11.2001 by giving following reasons had continued with that very departmental proceeding no. 1/97 in which the final order dated 13.7.1999 had been earlier passed as is apparent from the following extract of Annexure:-1 the show-cause notice dated 28.11.2005:-

"ज्ञापांक 2700/
डी0पी0–1–97
मुख्यालय, बिहारगृह रक्षा वाहिनी, पटना।
दिनांक 28 नवम्बर, 2005

सेवा में,
श्री नरेन्द्र नाथ मिश्रा,
सेवा निवृत कम्पनी कमांडर
फलैट न0–14, हनुमाननगर,
न्यू पूनाईचक, पटना–23

प्रसंगः— विभागीय कार्यवाही संख्या—1/97 में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य का प्रेषण।

विषयः— सी0डब्लु0 जे0 सी0 5227/02 में माननीय उच्च न्यायालय का आदेश।

आदेषानुसार उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय ने यह पाया है कि विभागीय कार्यवाही सं0—1/97 में आदेष पारित करने के पूर्व आपको संचालन पदाधिकारी के मंत्व्य की प्रति नहीं दी गयी थी एवं आपको अपना अंतिम बचाव समर्पित करने का मौका नहीं मिल पाया था। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने आपके विरूद्ध पारित आदेश चाहे तो इस त्रुटि को सुधारते हुए नये सीरे से इस विभागीय जॉच में कार्रवाई कर सकती है।

2. उल्लेखनीय है कि यह विभागीय कार्यवाही तब तक चलाई गयी थी, जब आप सेवा में थे। इस बीच आप सेवा निवृत हो चुके है।

3. क्योंकि अब आप सेवा निवृत हो चुके हैं इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि उपरोक्त विभागीय कार्यवाही की पेंशन नियमावली के नियम 43 के तहत पेंशन कटौती/जप्ति के मामले में परिवर्तित किया जाए।

4. अतः संचालन पदाधिकारी के मंतव्य की प्रति भेजते हुए कहना है कि पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अंदर आप अपना स्पष्टीकरण समर्पित करें कि आपके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए क्यों नहीं आपके पेंशन की कटौती/जप्ति का आदेश पारित किया जाए।

अनुलग्नकः— संचालन पदाधिकारी का मंतव्य।

ह0/—
समादेष्टा
बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना।''

In the opinion of this Court, such a notice is in full conformity with the aforementioned judgment of the Full Bench of this Court in the case of Shambhu Saran (supra).

The reliance placed by the petitioner either on the judgment of the Apex Court in the case of Mohd. Idris Ansari or the judgment of

the learned Single Judge in the case of Kauleshwar Pd. Sharma (supra) is wholly misplaced, inasmuch as, neither in the case of Mohd. Idris Ansari (supra) the Apex Court nor this Court in the case of Kauleshwar Prasad Sharma (supra) has held that once the employee would retire, he could not be subjected to the departmental proceeding which was already continuing before his retirement. In fact, the case of Mohd. Idris Ansari is an authority only for cases covered under proviso to Rule 43B which becomes applicable to an employee of the State Government against whom no departmental proceeding was ever drawn in his service tenure and was for the first time sought to be proceeded on a charge which had become not only stale but were barred by the period of four years in terms of the proviso to Rule 43B.

Such submission of the petitioner, is even otherwise fit to be rejected in the light of facts of his onw case because admittedly the petitioner had stood superannuated on 31.1.2000 whereas the writ application was filed in the year 2002 and if in view of the averment made in the writ application, a liberty was given to the respondents, as was definitely given in the

order of this Court dated 7.9.2005, while remitting the matter back to the disciplinary authority to proceed against the petitioner afresh, he ought to have filed an appeal against that part of the order of this Court. In absence of any order overruling or setting aside the operative portion of the order dated 7.9.2005 in C.W.J.C. No. 5227 of 2002, the earlier direction/liberty given by this Court while remitting the proceeding to the disciplinary authority in the aforesaid order of this Court dated 7.9.2005 being an inter-parte order cannot be overcome muchless indirectly assailed by the petitioner in the next round of litigation where an order of punishment again has been passed after considering the show-cause reply filed by him.

In fact, the judgment of the Apex Court in the case of ***Managing Director, ECIL, Hyderabad & Ors. Vs. B. Karunakar & Ors.*** reported in ***1993(4)SC 727*** itself lays down that in the event of non-supply of the enquiry report, the proceedee cannot be exonerated from the charge rather the proceeding has to start again from the stage of supply of the enquiry report.

In that view of the matter as well, it

would be difficult for this Court to accept the aforesaid submission of the petitioner, which actually was his main line of attack to the impugned order of punishment. In this context, learned counsel for the State has also rightly pointed out that the petitioner's prayer infact for deleting the last paragraph of the order dated 7.9.2005 in C.W.J.C. No. 5227 of 2002 of the Court remitting the enquiry back to the disciplinary authority despite being assailed and sought to be reviewed at the instance of the petitioner in Civil Review No. 209 of 2005 was dismissed by this Court on 11.9.2008 holding such review application itself to be wholly frivolous in nature. In fact, once the civil review application of the petitioner against the order of this Court dated 7.9.2005 was dismissed, it must be held that the direction given by this Court in the last paragraph to the extent

> *"However, the matter is remitted back to the disciplinary authority to proceed in the matter afresh, if so advised"*

got reaffirmed and the same would now definitely stare in the face of the petitioner and stand as a bar against him to raise a plea

as to raise the question of jurisdiction of the authority as with regard to the alleged infirmity and error in proceeding against the petitioner by issuing a show-cause notice dated 28th November, 2005 in the light of the aforesaid order of remand and liberty given in the order of this Court dated 7.9.2005.

The petitioner next submitted that the order of punishment was harsh, inasmuch as, the authority had not only directed for recovery of amount from his pension but had also held the petitioner to be not at all entitled for payment of any amount of T.A. Bill in question.

In this context, this Court will have to record that the charges against the petitioner were quite serious in nature and were also proved in course of departmental proceeding by production of both oral and documentary evidence. Thereafter, the following findings were recorded by the enquiry officer in respect of each of the charges:-

"विश्लेषण एवं निष्कर्ष :– गवाओं के बयान तथा आरोपित कंपनी कमांडर द्वारा समर्पित प्रारंभिक स्पष्टीकरण के आरोप में निम्नलिखित निष्कर्ष निकलता है :–

1. *आरोप संख्या 1 के संबंध में अपने प्रारंभिक स्पष्टीकरण में आरोपित कं0क0 ने यह तो स्पष्ट किया है कि उनके यात्रा भत्ता विपत्र को धनबाद होमगार्ड कार्यालय में आवंटन के साथ निकासी हेतु मुख्यालय के ज्ञापांक 3773 दिनांक 16.9.93 को भेजी गयी। परन्तु उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट नहीं कर सके हैं कि जिला समादेष्टा, धनबाद (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी) के द्वारा यात्रा भत्ता पारित नहीं कराकर प्रमंडलीय समादेष्टा/समादेष्टा, विषेषगण से क्यों पारित कराया गया। जिला समादेष्टा,*

धनबाद ने अपने ज्ञापांक 247 दि0 19.9.93 में यह लिखा है कि इन्होंने यात्रा भत्ता विपत्र को जिला समादेष्टा, धनबाद से आकलन नहीं कराकर प्रमंडलीय समादेष्टा हजारीबाग द्वारा करायी गयी। इसमें यही निष्कर्ष निकलता है कि जिला समादेष्टा, धनबाद के जानकारी के वगैर यात्रा भत्ता विपत्र को प्रमण्डलीय समादेष्टा, हजारीबाग से पारित कराया गया। इस यात्रा भत्ता विपत्र में अंकित तथ्यों के सही या गलत होने की जितनी जानकारी जिला समादेष्टा, धनबाद को हो सकती थी वह प्रमण्डलीय समादेष्टा, हजारीबाग को कतई नहीं होती।

2. आरोप सं0 2 के सम्बन्ध में आरोपित कंपनी कमांडर का तर्क मान्य नहीं हो सकता। क्योंकि आरक्षी हस्तक नियम के अनुसार निजी दैनन्दिनी की एक प्रति इनके पास होना चाहिये। (आरक्षी हस्तक नियम 64,87,448,626 तथा 1297) इनका यह कहना कि सभी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही प्रमण्डलीय समादेष्टा, हजारीबाग ने उनके यात्रा भत्ता विपत्र को पारित किया था। परन्तु यह यात्रा धनबाद में की गयी थी और धनबाद में एक जगह से दूसरे जगह की दूरी के संबंध में जो जानकारी जिला समादेष्टा, धनबाद को हो सकती थी वह प्रमंडलीय समादेष्टा, हजारीबाग को नहीं हो सकती।

3. तीसरे आरोप के संबंध में आरोप कं0क0 ने लिखा है कि यात्रा भत्ता विपत्र का कालम 22 कहाँ फटा उनको नहीं मालूम है। वे यात्रा भत्ता कार्यालय में सुपुर्द करने के वाद उसके संरक्षक नहीं थे। कालम नं0 22 को फाड़ने के पीदे किसी का भी क्या मंसा रहा होगा यह स्पष्ट नहीं है। परंतु जिन पृष्ठों में कॉलम 22 मौजूद है उसके अनतर्गत कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। यात्रा भत्ता विपत्र के जिन पृष्ठों कालम 22 फाड़ा गया है उन यात्रा भत्ता विपत्र के कालम 11 में कुछ लिखकर मिटाया गया लगता है तथा उस पर काला तथा लाल सयाही से Motor cycle लिखा गया है। कालम नं0 22 के फटे हुये अंश का कुछ मिलीमीटर अंश बचा हुआ है जिसपर कुछ लिखा हुआ है। शायद इसी लिखे हुये अंश को हटाने की नियत से कालम 22 को फाड़ा गया प्रतीत होता है। आगे के पृष्ठों में कहीं–कहीं अस्पष्ट रूप से ट्रेकर शब्द लिखा हुआ दिखाई पड़ता है जिसके उपर मोटर साइकिल लिखा हुआ है। चूँकि ट्रेकर लिखकर कालम 22 में उसके किराया का भुगतान अंकित किया गया होगा। चूँकि ट्रेकर को मिटाकर मोटर साइकिल लिखने के वाद कालम 22 में ट्रेकर का किराया भरना उचित नहीं होता इसलिये उस कालम को फाड़कर हटा दिया गया है। गौरतलब बात यह है कि यात्रा भत्ता विपत्र के कालम 22 को केवल उन्हीं पष्ठों से फाड़ा गया है जिन पृष्ठों पर कुछ लिखा हुआ था। शेष पृष्ठों के कालम 22 में जहाँ कुछ भी नहीं लिखा है उसे नहीं फाड़ा गया है।

आरोप संख्या 4 के संबंध में आरोपी कं0क0 ने लिखा है कि उन्होंने यात्रा दोस्त के मोटर सायकिल से किया था। उन्होंने यह भी लिखा है कि धनबाद जिला के संचिका संख्या ए0–1–2–82–83 के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि उन्होंने दोस्तों का नाम तथा मोटर सायकिल का नम्बर लिखकर दे दिया था। यात्रा भत्ता विपत्र के संबंध में जिला समादेष्टा ने लिखा है कि यात्रा भत्ता विपत्र में दोस्त के मोटर सायकिल के प्रयोग करने का उल्लेख नहीं किया गया है। (पृष्ठ 1/प0) आरोपी कं0क0 ने ट्रेकर शब्द को मिटाकर उसके उपर मोटर सायकिल लिखने के संबंध में कुछ नहीं लिखा है।

आरोप सं0 5 के संबंध में आरोपी कं0क0 ने लिखा है कि कार्य की महता तथा उससे संतुष्ट होकर ही विभिन्न सक्षम पदाधिकारियों ने निकासी एवं भुगतान का

आदेश दिया था। परन्तु उनहोंने अपने प्रारंभिक स्पष्टीकरण में एक माह में कम से कम 2302 कि0मी0 तथा अधिकतम 8196 कि0मी0 यात्रा करने के औचित्य को सपष्ट नहीं किया है।

आरोप सं0 6 के संबंध में आरोपी कं0क0 ने लिखा है कि जो भी यात्रा आदेशानुसार उनके द्वारा किया गया है वह सही है। परन्तु इन्होंने विभागीय कार्यवाही के दौरान किसी भी स्तर पर यात्रा करने के संबंध में सक्षम पदाधिकारी का आदेश प्रस्तुत नहीं किया। आरोप संख्या 6 में सितम्बर 81 से दिसम्बर 82 तक कुल 16 माह में उनके द्वारा 83710 कि0मी0 यात्रा करने के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है।

आरोप सं0 7 के संबंध में आरोपी ने बिहार सेवा संहिता के नियम 255 का हवाला देते हुये मोटर ब्हैकिल द्वारा 240 कि0मी0 तक यात्रा को एक दिन में करने के मान्यता के संबंध में लिखा है बिहार सेवा संहिता के नियम 255 में स्थानान्तरण के संबंध में पद ग्रहण काल का उल्लेख है न कि यात्रा भत्ता के संबंध में। इन्होंने विभिन्न तिथियों में किये गये अपने काम के सम्बन्ध में अपने स्पष्टीकरण में कुछ नहीं लिखा है।

आरोप सं0 8 के संबंध में आरोपी का प्रारंभिक स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है। उनहोंने मुख्यालय द्वारा भुगतान हेतु आवंटन दिये जाने के आदेश को ही आधार बताया है परन्तु यात्रा भत्ता विपत्र की सत्यता, औचित्य तथा सही होने के संबंध में ना तो कोई अभिलेख ही प्रस्तुत किया है और न कि कोई बचाव पक्ष का गवाह।

आरोपी कं0क0 द्वारा विभिन्न तिथियों को प्रति परीक्षण में अभी तक 308 प्रश्न पुछे गये हैं। प्रति परीक्षण में पूछे गये प्रश्नों के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि प्रश्नों के तर्क से विषय वस्तु को गलत साबित करने का प्रयास किया गया है। यह विभागीय कार्यवाही तो अभिलेखगत विषयों पर आधारित है। इसमें उठाये गये आरोप के बिन्दुओं का निराकरण तो साक्ष्य एवं अभिलेखों के आधार पर ही संभव है जिसे आरोपी कंपनी कमांडर प्रस्तुत करने में सफल नहीं हुये हैं। प्रति परीक्षण में पूछे गये प्रश्नों से स्पष्ट होगा कि आरोपी का मंशा विभागीय कार्यवाही के आरोपों के विभिन्न बिंदुओं के समाधान के वनिस्पत माननीय उच्च न्यायालय के चल रहे केस को ध्यान में रखकर किया गया है। ऐसा विरोधाभास उनके प्रश्नों से जगह–जगह स्पष्ट होता है।

निष्कर्ष :–

1. *आरोप संख्या 1 में प्रमण्डलीय समादेष्टा, हजारीबाग द्वारा यात्रा भत्ता विपत्र पारित किया गया है यह उचित नहीं है। तत्का0 प्रमंडलीय समादेष्टा, हजारीबाग के इनका यात्रा भत्ता विपत्र पारित नहीं करना चाहिए था। उनके जैसे वरीय पदाधिकारी द्वारा यह जानने के बाद भी कि आरोपी के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला समादेष्टा, धनबाद है विपत्र पारित करना उचित नहीं माना जा सकता।*

2. *इस विभाग में आरक्षी हस्तक के नियम 64,87, 448, 626 तथा 1297 के अनुसार आरोपी को पी0एम0 फार्म नं0 5 में अपने निजी देनन्दिनी यात्रा के बाद देना है। इस देनन्दिनी की एक प्रति उनके पास रहेगी किये गये यात्रा के संबंध में सक्षम पदाधिकारी का आदेष होना नितान्त आवश्यक है, आरोपी द्वारा यह आदेश*

उपस्थापित नहीं किया गया है।

3. *यात्रा भत्ता नियम के कुछ पन्नों के कालम 22 फटे हुये हैं। इस कालम में अंकित कुछ विषेष बातों को हटाने की नियत से फाड़ा गया है। इसका मुख्य कारण यात्रा भत्ता विपत्र के कालम 11 में अंकित ट्रेकर और उसको मिटाकर मोटर सायकिल लिखना प्रतीत होता है क्योंकि पूर्व में ट्रेकर से यात्रा दिखाया गया है और उसी के अनुसार कालम 22 में उसका किराया भरा गया होगा। बाद में मोटर सायकिल लिखने के बाद उसकी सार्थकता को ध्यान में रखकर कालम 22 को फाड़ दिया गया होगा।*

4. *सितम्बर 81 से दिसंबर 82 तक कुल यात्रा 83710 कि0मी0 यात्रा की गयी है तथा इस बीच कुल 393 दिनों की विराम अवधि दर्शायी गयी है। आरोपी द्वारा किये गये यात्रा की दूरी तथा विराम की अवधि को देखकर ऐसा लगता है कि इनके उपर कोई नियंत्रण करने वाला पदाधिकारी नहीं था। इस तरह की यात्रा और मुख्यालय से बाहर विराम, एक अनुशासित कल में कदापि संभव नहीं है। ऐसा लगता है कि इनके स्वच्छन्द विचरण पर जिला समादेष्टा द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है। अतः यह यात्रा विश्वसनीय नहीं माना जा सकता।*

मंतव्य :–

आरोप संख्या 1 से 5 तक लगाये गये सभी आरोपों में कं0क0 नरेन्द्र नाथ मिश्र दोषी पाये जाते हैं।''

It has to be noted that none of these findings was sought to be even remotely questioned by the petitioner in his show-cause reply filed on 5.12.2005 which as explained earlier was only an essay on the scope of Rule 43 of Bihar Pension Rules or his understanding of the Supreme Court judgment in the case of Mohd. Idris Ansari (supra) or questioning the wisdom of the disciplinary authority to issue a show-cause notice to him along with a copy of the enquiry report.

Once, this Court would find that the charges against the petitioner in view of the

enquiry report were found to be proved, and the petitioner did not assail any of the findings recorded by the Enquriy Officer in his enquiry report, it would be difficult for this Court to hold that the order of punishment was excessive or perverse in nature. The petitioner cannot claim payment of his travelling allowance when there is a finding that he had submitted false T.A. Bills. In any event the scope of judicial review in a departmental proceeding is confined only to the procedural aspect and decision making process. This Court cannot re-appraise the evidence or record its opinion finding on the merits of charge as was held by the Apex Court in the case of ***B.C. Chaturvedi Vs. Union of India & Ors.*** reported in ***1995(6)SCC 749*** laying down the law on the subject in a most trite manner in the following words: -

> *"……………… Judicial Review is not an appeal from a decision but a review of the manner in which the decision is made. Power of judicial review is meant to ensure that the individual receives fair treatment and not to ensure that the conclusion which the authority reaches is necessarily correct in the eye of the court. When an inquiry is conducted on charges of misconduct by a public servant, the Court/Tribunal is concerned to determine*

whether the inquiry was held by a competent officer or whether rules of natural justice are complied with. Whether the findings or conclusions are based on some evidence, the authority entrusted with the power to hold inquiry has jurisdiction, power and authority to reach a finding of fact or conclusion. But that finding must be based on some evidence. Neither the technical rules of Evidence Act nor of proof of fact or evidence as defined therein, apply to disciplinary proceeding. When the authority accepts that evidence and conclusion receives support there from, the disciplinary authority is entitled to hold that the delinquent officer is guilty of the charge. The Court/Tribunal in its power of judicial review does not act as appellate authority to reappreciate the evidence and to arrive at its own independent findings on the evidence. The Court/Tribunal may interfere where the authority held the proceedings against the delinquent officer in a manner inconsistent with the rules of natural justice or in violation of statutory rules prescribing the mode of inquiry or where the conclusion or finding reached by the disciplinary authority is based on no evidence. If the conclusion or finding be such as no reasonable person would have ever reached, the Court/Tribunal may interfere with the conclusion or the finding, and mould the relief so as to make it appropriate to the facts of each case.

The disciplinary authority is the sole judge of facts. Where appeal is

presented, the appellate authority has coextensive power to reappreciate the evidence or the nature of punishment. In a disciplinary inquiry, the strict proof of legal evidence and findings on that evidence are not relevant. Adequacy of evidence or reliability of evidence cannot be permitted to be canvassed before the Court/Tribunal. In Union of India V. H.C. Goel this Court held at p. 728 that if the conclusion, upon consideration of the evidence reached by the disciplinary authority, is perverse or suffers from patent error on the face of the record or based on no evidence at all, a writ of certiorari could be issued.

....

....

....

A review of the above legal position would establish that the disciplinary authority, and on appeal the appellate authority, being fact-finding authorities have exclusive power to consider the evidence with a view to maintain discipline. They are invested with the discretion to impose appropriate punishment keeping in view the magnitude or gravity of the misconduct. The High Court/Tribunal, while exercising the power of judicial review, cannot normally substitute its own conclusion on penalty and impose some other penalty. If the punishment imposed by the disciplinary authority or the appellate authority shocks the conscience of the High Court/Tribunal, it would appropriately mould the relief, either directing the

authority or the appellate authority shocks the conscience of the High Court/Tribunal, it would appropriately mould the relief, either directing the disciplinary/ appellate authority to reconsider the penalty imposed, or to shorten the litigation, it may itself, in exceptional and rare cases, impose appropriate punishment with cogent reasons in support thereof."

In the opinion of this Court, the petitioner in fact has been given very lenient punishment in respect of a very serious proven charge of misconduct concerning his honesty and integrity and that definitely would now need no interference of this Court.

This application, being thus devoid of any merit, must be and is hereby dismissed.

(Mihir Kumar Jha, J.)

Patna High Court
Dated the 18th September 2009
Rsh/A.F.R.